



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसारात्मक

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 231] नई दिल्ली, ब्रह्मवार, जून 27, 1973/प्राप्तांक 6 1895

No. 231] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 1973/ASADHA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह प्राप्तगत संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June 1973

S.O. 356 (E).—Whereas the Central Government has, by its notified order in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S.O. 1482, dated the 31st March, 1971 issued under clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Board of Management consisting of Sarvashri R. V. Subrahmanian and S. K. Moitra to take over the Management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Gresham and Craven of India (Private) Limited, Calcutta (hereinafter in this notification referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified Order under section 18A,

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations, subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the industrial undertaking.
Section 224	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 225	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking, except that the auditor shall be appointed by the Central Government.

[No. 2/25/71-P.S. Cell/HM. I]
S. M. GHOSH Jt. Secy.

भारी उच्चोग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जून, 1973

का० प्रा० 356 (अ) .—यतः केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व श्रीद्योगिक विकास और आतंरिक व्यापार मंत्रालय में अपने अधिसूचित आदेश सं० का० प्रा० 1482, तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा जिसे उच्चोग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया है, मैमर्स शेषम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् श्रीद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक श्रीद्योगिक उपक्रम का संपूर्ण प्रबन्ध, प्रबन्धक-बोर्ड को, जिसमे संबंधी प्रार० वी० सुशाहाणियन और प्रा० के० मैत्रा है, उसमें विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राप्तिकृत किया है :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 अ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त ग्रन्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसमें उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) श्रीद्योगिक उपक्रम को उसी प्रकार लागू बना रहेगा जिस प्रकार वह धारा 18 के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उसे लागू था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956
के उपबन्ध

वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध श्रीद्योगिक उपक्रम में लागू होंगे ।

धारा 224

इस धारा के उपबन्ध श्रीद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।

धारा 225

इस धारा के उपबन्ध श्रीद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे, मिवाय इसके कि संपरीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

[सं० 2/25/71-पी०एस०मेल/ग्रंथ एम I]

एस० एस० घोष, संयुक्त सचिव, ।